

डॉ०हेमलता झोंडियाल,

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन ।

सेवार्थ,

निदेशक,

पर्यटन निदेशालय,

उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पर्यटन अनुभाग:

देहरादून दिनांक 09 अक्टूबर, 2007

विषय: जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत महारू देवता मंदिर लखस्यार का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में धनराशि की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-395/2-6-449/2006-07, दिनांक 7 दिसम्बर, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2006-07 में जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत महारू देवता मंदिर लखस्यार का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु तकनीकी परीक्षणोपरान्त रांस्तृत रु० 30.90 लाख (रुपये तीस लाख नब्बे हजार मात्र) की लागत के आगणनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2007-08 में रु० 10.00 लाख (रुपये दस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय करने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां बह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिससे व्यय करने के हेतु पूर्व राक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है; व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3-आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हैं की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करा लें।

4-कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार राक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5-कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6-एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार राक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7-कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के मध्य-नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8-कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

9-आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

10-निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

11-कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी तथा बाढ़ व नदी के बहाव आदि से सम्बन्धित सभी बिन्दुओं का परीक्षण निर्माण एजेन्सी द्वारा निर्माण से पूर्व कर लिया जाएगा जिससे भविष्य में किसी प्रकार की समस्या न हो।

12-उक्त स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31-03-2008 तक पूर्ण उपयोग कर धनराशि की वित्तीय/मांतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा तदोपरान्त ही अवशेष अथवा दूसरी किरत अवमुक्त की जायेगी।

13-कार्य प्रारम्भ के समय सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी कार्यस्थल पर इस आशय का एक साईन बोर्ड स्थापित करेगा कि उक्त योजना/कार्य पर्यटन विभाग, उत्तरांचल के सौजन्य से किया जा रहा है, योजना प्रारम्भ करने का

दिनांक

। समय, इसकी लागत, पूर्ण करने का समय तथा कार्यदायी संस्था का विवरण भी अंकित किया जायेगा। सम्बन्धित जिला पर्यटक विकास अधिकारी उक्त कार्य का समय-समय पर भौतिक निरीक्षण कर कार्य की भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह शासन को अवगत करायें एवं कार्य पूर्ण होने की सूचना व योजना का फोटोग्राफस अवश्य शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध करायेगा।

14-कार्यदायी संस्था का निर्धारण अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की ओर निर्गत शासनादेश संख्या-39/XXVII/2007 14 अंगरत, 2007 के अनुसार ही किया जायेगा।

15-योजना पर धनराशि तभी व्यय की जायेगी जब योजना हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाय तथा राज्य सेक्टर योजनाओं हेतु निर्गत अन्य संगत दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाय।

16-उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-आयोजनागत-796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-02-अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेट प्लान-01-पर्यटन विकास की नई परियोजनाएं-24-बृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

17-उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-463/XXVII(2)/2007, दिनांक 01 अक्टूबर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(डॉ० हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

संख्या- 100 /VI/2007-5(6)2006, टी0सी0 तदुद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2-वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 3-जिलाधिकारी, देहरादून।
- 4-निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
- 5-निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
- 6-निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 7-जिला पर्यटन विकास अधिकारी, देहरादून।
- 8-वित्त अनुभाग-2,
- 9-श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त।
- 10-अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 11-एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
- 12-गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(डॉ० हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।